

मेसर्स मेला राम एंड संस

बनाम

आयकर आयुक्त, पंजाब

[एस.आर. दास, सी.जे., भगवती और वेंकटराम

अय्यर जे.जे.]

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का XI), ss.23,30(1)  
(2),31,33-आयकर निर्धारण-माँग का नोटिस-विरुद्ध अपील मूल्यांकन-  
अपीलीय सहायक आयुक्त में प्राप्त कार्यालय समय से बाहर-विलंब क्षमा हेतु  
प्रार्थना अस्वीकृत- सहायक आयुक्त का अपील खारिज करने का आदेश  
समय का-चाहे एक एस के तहत. 30(2) या धारा के अंतर्गत। अधिनियम  
की धारा 31- क्या अपील उसके लिए सक्षम है. अपीलकर्ता फर्म ने इसका  
आकलन करने वाले आदेशों के खिलाफ अपील दायर की वर्ष 1945-1946  
के लिए आयकर और सुपर-टैक्स के लिए और 1946-1947 एस द्वारा  
निर्धारित समय से परे 30(2) का आयकर अधिनियम. अपीलें क्रमांकित  
थीं, और नोटिस थे के तहत उनकी सुनवाई के लिए जारी किया गया। 31  
की सुनवाई में अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपील विभाग ने आपत्ति  
ली कि अपीलें रोक दी गयीं समय तक। अपीलार्थी ने विलम्ब क्षमा करने  
की प्रार्थना की, परन्तु जिसे अस्वीकार कर दिया गया, और अपीलें समय  
के साथ खारिज कर दी गईं- वर्जित. इसके बाद अपीलकर्ता ने इसके

खिलाफ अपील दायर की के तहत ट्रिब्यूनल को बर्खास्तगी के आदेश अधिनियम के 33, और ट्रिब्यूनल ने उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया कि सहायक आयुक्त के आदेश प्रभावी थे के अंतर्गत पारित किया गया। 30(2) और धारा के अंतर्गत नहीं। अधिनियम के 31 और धारा के तहत उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती अधिनियम के 33 एस के तहत एक संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 66(1) पर विचार किया कि अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश थे एस के तहत बनाया गया। 30(2) और धारा के तहत अपील योग्य नहीं थे। 33 का अधिनियम।

उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील पर प्रश्न निर्धारण के लिए यह था कि क्या अपील को खारिज करने का आदेश दिया गया थाएस के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। 30 क्योंकि समय से बाहर एस के अंतर्गत एक था। 30(2) या धारा के अंतर्गत। अधिनियम के 31 क्योंकि यदि यह वहां पूर्व था क्या इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई; यदि यह बाद वाला होता तो यह के तहत अपील करने के लिए खुला था। 33 .माना कि अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश हैं एस के भीतर गिर गया 31 .अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और एक प्राणी है कानून का. धारा 30(1) निर्धारिती को इसका अधिकार प्रदान करती है। कुछ आदेशों और मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपीलएस के तहत 23 उनमें से एक है. इसलिए अपीलकर्ता के पास एस के तहत वास्तविक अधिकार

30(1) के विरुद्ध अपील करना आयकर अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेश।

समय से बाहर प्रस्तुत की गई अपील एक अपील और एक आदेश है इसे कालबाधित मानकर खारिज करना अपील में पारित किया गया है धारा 31 ही सुनवाई से संबंधित एकमात्र प्रावधान है अपीलों का निपटान और यदि किसी अपील को खारिज करने का आदेश दिया जाता है वर्तमान मामले में सीमा से वर्जित है अपील यह एस के अंतर्गत आना चाहिए । 31 और एस के रूप में. 33 प्रदान करता है ए के तहत पारित सभी आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार 31 यह अपील योग्य भी होना चाहिए एस के भीतर गिरना 31 यह आवश्यक नहीं है कि आदेश को स्पष्ट रूप से स्वयं को संबोधित करना चाहिए और गुणों पर निर्णय लेना चाहिए मूल्यांकन का और यह पर्याप्त है कि का प्रभाव आदेश मूल्यांकन की पुष्टि करने के लिए है जब अपील की जाती है प्रारंभिक बिंदु पर खारिज कर दिया गया।परिसीमा के आधार पर अपील खारिज करने का आदेश इसे स्वीकार किए जाने के बाद यह एस के अंतर्गत एक है। 31 , यद्यपि वहाँ मूल्यांकन की योग्यता पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए माना गया कि अपीलीय सहायक के आदेश आयुक्त ने माना कि पर्याप्त कारण नहीं थे विलंब को माफ करने और समय के साथ अपीलों को खारिज करने के लिए के तहत पारित आदेश वर्जित होंगे। और खुला रहेगा अपील करने के लिए, और इससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या बर्खास्तगी के आदेश पहले किये

गये थे या बाद में अपीलें स्वीकार कर ली गईं। आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम माउंट आर. एस. अर. अरुणाचलम चेट्टियार, ([1953] एससीआर 463), समझाया गया। केस-कानून पर चर्चा हुई.

निर्णय:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 17/1954

पंजाब उच्च न्यायालय के सिविल संदर्भ संख्या 2/1951 में 11 जून 1951 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से हरदयाल हार्डी और सरदार सिंह।प्रतिवादी की ओर से भारत के सॉलिसिटर-जनरल सीके दफ्तरी (जीएन जोशी और आरएच डेबर, उनके साथ) 1956. 21 फरवरी। अदालत का फैसला वेंकटरियामा अय्यर जे. द्वारा सुनाया गया - अपीलकर्ता पंजाब के लुधियाना में कारोबार करने वाली एक फर्म है।आयकर अधिकारी ने 1945-1946 के लिए इसकी आय रुपये आंकी। 71,186, और 17-9-1947 को उस पर रुपये की मांग का नोटिस दिया गया। आयकर और सुपर-टैक्स के कारण 29,857-6-0।अपीलकर्ता ने मूल्यांकन के विरुद्ध अपील दायर की, और यह वास्तव में 5-11-1947 को अपीलीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुई। तब यह 19 दिनों के लिए समय से बाहर हो गया था; लेकिन अपील संख्या 86 के रूप में पंजीकृत की गई थी, और धारा 31 के तहत सुनवाई के लिए नोटिस 13-12-1947 के लिए जारी किया गया था, और कई

स्थगनों से गुजरने के बाद, वास्तव में 1-10-1948 को इसकी सुनवाई हुई थी। वर्ष 1946-1947 के लिए, आयकर अधिकारी ने फर्म की आय रुपये पर मूल्यांकन किया। 1,09,883, और 29-9-1947 को उस पर रुपये की मांग का नोटिस दिया गया। आयकर और सुपर-टैक्स के कारण 51,313-14-0। अपीलकर्ता ने इस मूल्यांकन के खिलाफ एक अपील दायर की, और यह वास्तव में 5-11-1947 को अपीलीय सहायक आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुई थी, और तब इसमें 7 दिन का समय था। इसे संख्या 89 के रूप में पंजीकृत किया गया था, और धारा 31 के तहत सुनवाई के लिए 24-6-1948 को नोटिस जारी किया गया था। आखिरकार, 1-10-1948 को अपील संख्या 86 के साथ इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में, विभाग ने आपत्ति जताई कि अपीलें समय से पहले प्रस्तुत की गईं, और इसलिए खारिज की जा सकती हैं। अपीलकर्ता ने इस आधार पर देरी की माफी की प्रार्थना की कि देश के विभाजन के बाद स्थितियाँ बहुत अस्थिर थीं, कर्फ्यू आदेश घोषित किया गया था और लागू था, और डाकघर पंजीकृत पत्रों को स्वीकार नहीं करता था, और यह कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर यातायात बंद कर दिया गया था, और इन असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, समय पर अपील प्रस्तुत नहीं करने का यह पर्याप्त कारण था। 31-12-1948 को अपीलीय सहायक आयुक्त ने दोनों अपीलों में आदेश पारित किया, यह मानते हुए कि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था, और उन्हें प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया गया। इन आदेशों को धारा 30(2) के साथ पठित धारा 31 के तहत पारित किया जाना बताया गया था। इन आदेशों के

खिलाफ, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 33 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, जिसने अपने आदेश दिनांक 4-4-1950 द्वारा उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया कि सहायक आयुक्त के आदेश वास्तव में धारा 30 (2) के तहत पारित किए गए थे। और धारा 31 के तहत नहीं और धारा 33 के तहत उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, आवेदन पर-

अपीलकर्ता के कथन के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के तहत पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया:

"क्या मामले की परिस्थितियों में अपीलीय सहायक आयुक्त के वर्ष 1945-1946 और 1946-1947 के आकलन के खिलाफ अपीलों को खारिज करने के आदेशों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की गई थी"। यह संदर्भ खोसला और हरनाम सिंह जेजे द्वारा दाढ़ी द्वारा दिया गया था, जिन्होंने दीवान चंद बनाम आयकर आयुक्त (1) में उस अदालत के पहले के फैसले का पालन करते हुए कहा था कि अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश धारा 30 (2) के तहत थे और अपील योग्य नहीं थे। धारा 33 के तहत इस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने का प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील करने के लिए आवेदन किया और अनुमति प्राप्त की, और इस तरह अपील अमेरिका के समक्ष

आती है। अब प्रश्न से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है। धारा 30(1) निर्धारिती को उसमें निर्दिष्ट धाराओं के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करती है। धारा 30(2) में प्रावधान है कि अपील आम तौर पर मूल्यांकन के आदेश के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन अपीलीय सहायक आयुक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण बताया है। यह उस अवधि के भीतर है। धारा 30(3) में प्रावधान है कि "अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी"। धारा 31(1) अधिनियमित करती है कि "अपीलीय सहायक आयुक्त अपील की सुनवाई के लिए एक दिन और स्थान तय करेगा, और समय-समय पर सुनवाई स्थगित कर सकता है"। धारा 31(3) उन आदेशों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें अपील में पारित किया जा सकता है क्योंकि वे अधिनियम की एक या अन्य धाराओं के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध निर्देशित होते हैं जो धारा 30(1) में निर्दिष्ट हैं। जब अपील धारा 23 के तहत मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ है-और यही हम मानते हैं-

(1) (1951] 20 1 टीआर 621, इस अपील से संबंधित - यह धारा 31(3) , खंड (ए) और (बी) में प्रदान किया गया है कि अपील के निपटान में अपीलीय सहायक आयुक्त (ए) पुष्टि कर सकता है, मूल्यांकन को कम करें, बढ़ाएं या रद्द करें, या (बी) मूल्यांकन को अलग रखें और निर्देश दें।

आयकर अधिकारी को ऐसी आगे की पूछताछ करने के बाद एक नया मूल्यांकन करने का निर्देश दें, जैसा आयकर अधिकारी उचित समझे। धारा 33(1) अधिनियमित करती है कि, "धारा 28 या धारा 31 के तहत अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति करने वाला कोई भी निर्धारिती उस तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है जिस दिन उसे ऐसा आदेश सूचित किया जाता है।" संक्षेप में कहा गया है, धारा 30 एक अधिकार प्रदान करती है निर्धारिती पर अपील, धारा 31 अपील की सुनवाई और निपटान का प्रावधान करती है, और धारा 33 धारा 31 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ आगे अपील करने का अधिकार प्रदान करती है , अब, इन प्रावधानों पर सवाल यह है कि क्या धारा के तहत प्रस्तुत अपील को खारिज करने वाला कोई आदेश है 30 क्योंकि समय से बाहर धारा 30(2) या अधिनियम की धारा 31 के तहत एक है। यदि यह पूर्व है, तो इसके विरुद्ध कोई अपील उपलब्ध नहीं है; यदि यह उत्तरार्द्ध है, तो यह धारा 33 के तहत अपील करने के लिए खुला है। इस प्रश्न पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों और यहां तक कि एक ही उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के बीच भी तीव्र मतभेद रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि जब कोई अपील समय से बाहर प्रस्तुत की जाती है, और धारा 30(2) के तहत देरी को माफ करने का कोई आदेश नहीं है, तो कानून में, अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष कोई अपील नहीं है, और वह एक आदेश है उनके द्वारा अपील को खारिज करना धारा 31 के अंतर्गत नहीं आता है और अपील योग्य नहीं है: आयकर आयुक्त बनाम मैसूर

आयरन एंड स्टील वर्क्स (1) और केके पोरबंदरवाला बनाम आयकर आयुक्त (2); लेकिन यदि धारा 30(2) के तहत माफी का आदेश दिए जाने के बाद अपील स्वीकार की जाती है, तो बाद में परिसीमा के आधार पर इसे खारिज करने वाला आदेश धारा 31 के तहत एक होगा और धारा 33 के तहत अपील योग्य होगा और परिणाम होगा यह तब भी समान है जब अपील (1) के बिना स्वीकार की जाती है। [1949] 17 आईटीआर 478, (2) [1952] 21 आईटीआर 63।

धारा 30(2) के तहत माफी का कोई आदेश : चंपालाल ए शर्मा बनाम आयकर आयुक्त(1)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है, और माना है कि देरी को माफ करने से इनकार करने और किसी अपील को स्वीकार किए जाने से पहले खारिज करने का आदेश धारा 31 के तहत नहीं था और अपील योग्य नहीं था: शिवनाथ प्रसाद बनाम आयकर आयुक्त के मामले में , सेंट्रल और यूपी(3) और म्यूनिसिपल बोर्ड, आगरा बनाम आयकर आयुक्त, यूपी(3); लेकिन अपील को स्वीकार किए जाने के बाद समय-बाधित के रूप में खारिज करने वाला वह एआईएल आदेश धारा 31 के तहत एक था और अपील योग्य था: मोहम्मद। नैन मो. आलम बनाम आयकर आयुक्त (1)। पंजाब उच्च न्यायालय ने शिवनाथ प्रसाद बनाम आयकर आयुक्त, मध्य और यूपी (2) और आयकर आयुक्त बनाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स (5) के बाद माना है कि जब अपीलीय सहायक आयुक्त देरी को माफ करने से इनकार कर देता है और

अपील को खारिज कर देता है , यह धारा 30(2) के तहत एक है और अपील योग्य नहीं है। इसने आगे माना है कि भले ही अपील को बिना माफी के आदेश के स्वीकार कर लिया गया हो और परिसीमा के आधार पर सुनवाई में खारिज कर दिया गया हो, यह धारा 31 के तहत नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम की योजना में विचार किया गया है कि इसके तहत एक आदेश पारित किया जाना चाहिए। वह अनुभाग मूल्यांकन की खूबियों से संबंधित होना चाहिए। यह इस निर्णय पर आधारित है कि अपील के तहत निर्णय आधारित है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि दीवान चंद बनाम आयकर आयुक्त (6) के फैसले से जनरल एजेंसियां बनाम आय में पंजाब उच्च न्यायालय के हालिया फैसले से असहमति जताई गई थी। कर आयुक्त (7) आयकर आयुक्त बनाम शहजादी बेगम मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि देरी को माफ करने और अपील को खारिज करने का आदेश धारा 31 के तहत एक है , चाहे वह अपील स्वीकार किए जाने से पहले किया गया हो या बाद में, और यह एक अपील है जो समय से बाहर दायर किया गया है, फिर भी, धारा 31 के प्रयोजनों के लिए एक अपील है , और इसे खारिज करने वाला आदेश धारा 33 के तहत अपील योग्य होगा । गौर मोहन में (1) [1953] 23 आईटीआर 464, (3) [1951] 19 आईटीआर 63।

(5) [1949] 17 आईटीआर 478।

(7) ए.आई. आर. 1956 पंजाब 26.

(2) [1936] 3 आईटीआर 200।

(4) [1951] 19 आईटीआर 58।

(6) [1951] 20 आईटीआर 62।

(8) [1952] 21 आईटीआर 1.

मुलिक बनाम कृषि आयकर आयुक्त (1), कलकत्ता उच्च न्यायालय, पूरी चर्चा के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी भी स्तर पर परिसीमा के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश धारा 31 के अंतर्गत आता है। अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों में व्यक्त विचारों का उल्लेख करना अनावश्यक है, क्योंकि अब चर्चा का मुद्दा सीधे तौर पर वहां निर्णय के लिए नहीं उठा है प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया सही है। हम इससे शुरू करते हैं कि धारा 33 के तहत केवल धारा 31 के तहत आदेश ही अपील योग्य हैं। इसलिए सवाल यहीं तक सीमित हो जाता है कि क्या देरी को माफ करने से इनकार करने वाला और अपील को समयबाधित मानकर खारिज करने वाला आदेश धारा 31 के तहत एक आदेश है। यह तब होगा, जब इसे मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील में पारित किया जाता है, और वह ऐसा है जो इसकी पुष्टि करता है। अब, कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचार दो बिंदुओं पर केंद्रित हैं: (1) जब कोई अपील समय से बाहर प्रस्तुत की जाती है और धारा 30(2) के तहत देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया है, तो

इसे समय के रूप में खारिज करने वाला आदेश है -अपील में पारित एक वर्जित; और (2) यदि ऐसा है, तो क्या ऐसा आदेश धारा 31(3)(ए) के अंतर्गत मूल्यांकन की पुष्टि करता है ?

पहले बिंदु पर, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना है कि किसी अपील को स्वीकार करने के बाद उसे कालबाधित मानकर खारिज करने का आदेश धारा 31 के तहत आता है, लेकिन स्वीकार किए जाने से पहले पारित किया गया समान आदेश धारा 31 के तहत आता है। धारा 30(2) . इस अंतर का अनुपात यह बताया गया है कि कानून में कोई अपील नहीं होती है जब तक कि इसे समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, और यदि समय से परे प्रस्तुत किया जाता है, तो देरी को माफ नहीं किया जाता है। आयकर आयुक्त बनाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स (2), चागला में, मुख्य न्यायाधीश ने स्थिति इस प्रकार बताई:

"किसी निर्धारित के पास उस अपील को स्वीकार करने के लिए अपीलीय सहायक आयुक्त से किसी भी आदेश की आवश्यकता के बिना तीस दिनों के भीतर अपील पेश करने का वैधानिक अधिकार है। लेकिन यदि निर्धारित समय समाप्त हो जाता है, तो अपील पेश करने का वह वैधानिक अधिकार चला जाता है; और एक अपील इस पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब इसे अपीलीय सहायक

आयुक्त द्वारा देरी को माफ करने के बाद स्वीकार किया जाए। (1) [1952] 22 आईटीआर 131।

(2) [1949] 17 आईटीआर 478।

इसलिए इस मामले में अपील स्वीकार करने से पहले, अपीलीय सहायक आयुक्त का एक आदेश आवश्यक था कि देरी माफ कर दी गई थी और ऐसा आदेश दिए जाने पर ही अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा विचार किया जा सकता था। अब धारा 31 केवल ऐसी अपीलों से संबंधित है जो निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाती हैं या देरी माफ होने के बाद स्वीकार की जाती हैं, और अपील की सुनवाई के संबंध में धारा 31 में निर्धारित प्रक्रिया केवल ऐसी अपीलों पर लागू होती है। इसलिए, मेरी राय में, जब अपीलीय सहायक आयुक्त ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया, तो उसके सामने कोई अपील नहीं थी जिसे वह सुन सकता था और अधिनियम की धारा 31 के तहत निपटान कर सकता था। धारा 33 तब अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा धारा 28 या धारा 31 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ निर्धारिती को अपील करने का अधिकार देती है। इसलिए विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 30 के तहत

अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ निर्धारिती को अपील का अधिकार नहीं दिया।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील अंतिम टिप्पणी की सत्यता पर विवाद करते हैं कि अपीलीय सहायक आयुक्त का देरी को माफ करने से इनकार करने का आदेश धारा 30(2) के तहत एक है, और तर्क देते हैं कि उस धारा के तहत पारित किया जा सकने वाला एकमात्र आदेश एक बहाना था विलंब, और इसे माफ करने से इनकार करने वाला आदेश इसके बाहर होगा, और ऐसा आदेश केवल धारा 31 के तहत ही दिया जा सकता है। हमें इस विवाद को स्वीकार करना कठिन लगता है। जब किसी प्राधिकारी को अपने विवेक से प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो अनुदान में यह अनिवार्य रूप से निहित होता है कि वह इसका प्रयोग उस तरीके से कर सकता है जैसी परिस्थितियाँ आवश्यक हो सकती हैं। और यदि अपीलीय सहायक आयुक्त के पास देरी को माफ करने का विवेक है, तो उसके पास उचित मामलों में ऐसा करने से इनकार करने का भी विवेक है। इसलिए हमारी राय है कि देरी को माफ करने से इंकार करना धारा 30 (2.) के तहत एक आदेश है।

लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या आयकर आयुक्त बनाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स (1) और केके पोरबंदरवाला बनाम आयकर आयुक्त (2) में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि एक अपील जो सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है, कानून की नजर में, कोई अपील नहीं,

जब तक कि देरी की माफी न हो, और इसके परिणामस्वरूप, उस पर पारित आदेश को अपील में पारित नहीं माना जा सकता है, ताकि धारा 31 के अंतर्गत आना सही हो। अब, अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है, और कानून का एक अंग है। धारा 30(1) निर्धारिती को कुछ आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करती है, और धारा 23 के तहत मूल्यांकन का आदेश उनमें से एक है। इसलिए अपीलकर्ता के पास धारा 30(1) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ अपील करने का वास्तविक अधिकार था। फिर, हम धारा 30(2) पर आते हैं, जो एक सीमा अवधि लागू करती है जिसके भीतर इस अधिकार का प्रयोग किया जाना है। यदि कोई अपील उस समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो क्या धारा 30(1) के तहत प्रावधान के अनुसार वह अपील नहीं रह जाएगी? यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सीमा के नियम, विशेषण कानून के क्षेत्र से संबंधित हैं, और वे केवल उपाय को रोकने के लिए काम करते हैं, लेकिन अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं। इसलिए, धारा 30(1) के अनुसार की गई अपील, कानून की नजर में एक अपील होनी चाहिए, हालांकि धारा 30(2) में उल्लिखित अवधि से परे प्रस्तुत किए जाने पर इसे एक सीमा तक खारिज किया जा सकता है। कानून में ऐसा प्रावधान हो सकता है कि निर्धारित सीमा अवधि के अंत में, अधिकार समाप्त हो जाएगा, उदाहरण के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 28; लेकिन यहां ऐसा कोई नहीं है। दूसरी ओर, धारा 30(1) के तहत अपील का अधिकार प्रदान करने और धारा 30(2) के तहत अलग

से उसके अभ्यास के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने में , विधायिका ने इसके तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त भेद को बनाए रखने का इरादा दिखाया है। वास्तविक अधिकार क्या है और प्रक्रियात्मक कानून का मामला क्या है, के बीच सामान्य कानून। नागेंद्रनाथ डे बनाम सुरेश चंद्र डे(3) में सर दिनशॉ मुल्ला ने लिमिटेसन एक्ट के अनुच्छेद 182 के तीसरे कॉलम में 'अपील' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा : "सिविल प्रो- (1) [1949] में अपील की कोई परिभाषा नहीं है। ] 17 आईटीआर 478. (2) [1952] 21 आईटीआर 63. (3) 59 आईए 283, 287.

सीड्यूर कोड, लेकिन उनके आधिपत्य में कोई संदेह नहीं है कि किसी पक्ष द्वारा किसी अपीलीय, न्यायालय में किया गया कोई भी आवेदन, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए कहा जाता है, शब्द की सामान्य स्वीकृति के भीतर एक अपील है, और यह है यह किसी अपील से कम नहीं है क्योंकि यह अनियमित या अक्षम है"।

इन टिप्पणियों को राजा कुलकर्णी और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य (1) मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था और अपनाया गया था । प्रोमोथो नाथ रॉय बनाम डब्ल्यूए ली (2) में , प्रस्तुति में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन को खारिज करने के बाद एक आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज करने के आदेश को "अपील पर पारित" माना

गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 का अर्थ. इन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर, यह माना जाना चाहिए कि समय से पहले की गई अपील एक अपील है, और इसे समय-बाधित के रूप में खारिज करने वाला आदेश अपील में पारित किया गया आदेश है।

फिर, अगला सवाल यह है कि क्या यह अधिनियम की धारा 31 के तहत पारित आदेश है । वह धारा अपीलों की सुनवाई और निपटान से संबंधित एकमात्र प्रावधान है, और यदि किसी अपील को सीमा से वर्जित मानकर खारिज करने का आदेश अपील में पारित किया जाता है, तो इसे धारा 31 के अंतर्गत आना चाहिए । और चूंकि धारा 33 धारा 31 के तहत पारित सभी आदेशों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करती है , इसलिए यह अपील योग्य भी होना चाहिए। लेकिन फिर, यह तर्क दिया जाता है कि मूल्यांकन के खिलाफ अपील में धारा 31 (3) (ए) के तहत पारित किया जा सकने वाला एकमात्र आदेश वह है जो मूल्यांकन की पुष्टि करता है, कम करता है, बढ़ाता है या रद्द करता है, ऐसा आदेश केवल तभी दिया जा सकता है अपील की योग्यता पर विचार, और परिसीमा के आधार पर इसे खारिज करने का आदेश इस धारा के अंतर्गत नहीं है। दीवान चंद बनाम आयकर आयुक्त (3) में यही दृष्टिकोण अपनाया गया था । लेकिन अन्य सभी उच्च न्यायालयों के बीच व्यावहारिक रूप से एकमत राय है कि धारा के अंतर्गत आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आदेश को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाए और मूल्यांकन के गुणों पर निर्णय लिया जाए,

और यह पर्याप्त है कि प्रभाव आदेश का उद्देश्य मूल्यांकन की पुष्टि करना है

(1) [1954] एससीआर 384, 388। (2) एआईआर 1921 कैल। 415.

(3) [1951] 20 आईटीआर 621।

जैसे कि जब अपील प्रारंभिक बिंदु पर खारिज कर दी जाती है।  
आयकर आयुक्त बनाम शहजादी बेगम (1) में, सत्यनारायण राव, जे. ने  
कहा:

"यदि अपील को अक्षम मानकर खारिज कर दिया  
जाता है या इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि इसे  
समय से पहले दायर किया गया था और कोई पर्याप्त कारण  
स्थापित नहीं किया गया था, तो इसके परिणामस्वरूप उस  
आदेश की पुष्टि हो जाती है जिसके खिलाफ अपील की गई  
है"।

गौर मोहन मुलिक बनाम कृषि आयकर आयुक्त (2) में, बंगाल कृषि  
आयकर अधिनियम की धारा 34, 35 और 36 की व्याख्या करते हुए, जो  
भारतीय आय की धारा 30 , 31 और 33 के समान हैं- कर अधिनियम,  
चक्रवर्ती, जे. ने कहा: "मैं उस दृष्टिकोण को इस आधार पर रखूंगा कि  
आदेश, वास्तव में, मूल्यांकन की पुष्टि करता है या, किसी भी दर पर,  
अपील का निपटारा करता है और इस प्रकार धारा 35 के तहत एक आदेश  
था, क्योंकि वह क्या था अनुभाग वास्तव में अपील के निपटान या निष्कर्ष

पर विचार करता है और इसमें निर्दिष्ट आदेशों के रूप संपूर्ण नहीं हैं। एक अपीलीय आदेश, सीधे और स्वयं, मूल्यांकन की पुष्टि, या कम या वृद्धि या रद्द नहीं कर सकता है और फिर भी इसका निपटान कर सकता है अपील। यदि ऐसा होता है, तो यह महत्वहीन है कि क्या इसका आधार यह निष्कर्ष है कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है या यह निष्कर्ष है कि मामला समय विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है या दोनों"।

यह तर्क बॉम्बे और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी आधार है, जिसमें कहा गया था कि किसी अपील को स्वीकार किए जाने के बाद सीमा के आधार पर खारिज करने का आदेश धारा 31 के तहत एक है, हालांकि इसमें गुण-दोष पर कोई विचार नहीं किया गया है। आकलन। इस प्रकार, केके पोरबंदरवाला बनाम आयकर आयुक्त (3), चागला में, सीजे ने कहा:

"हालांकि अपीलीय सहायक आयुक्त ने गुण-दोष के आधार पर अपील नहीं सुनी और माना कि अपील परिसीमा द्वारा वर्जित थी, उनका आदेश धारा 31 के तहत था और उस आदेश का प्रभाव उस मूल्यांकन की पुष्टि करना था जो कि खराब था। आयकर अधिकारी"।

कोर्ट ऑफ वाइर्स बनाम कमिश्नर के विशेष प्रबंधक में (1) [1952]  
21 आईटीआर 1. (2) [1952] 22 आईटीआर 131. (3) [1952] 21  
आईटीआर 63।

आयकर (1) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह विचार "संभव है कि भले ही सीमा की अवधि धारा 30 के तहत निर्धारित की गई है और विस्तार देने की शक्ति भी उस धारा में दी गई है, लेकिन धारा के तहत वास्तव में शक्ति का प्रयोग किया जाता है 31 अपीलीय सहायक आयुक्त के रूप में जब वह परिसीमा की अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय लेता है तो यह कहा जा सकता है कि उसने मूल्यांकन की पुष्टि कर दी है।"

प्रतिवादी ने महाबीर प्रसाद निरंजनलाल बनाम आयकर आयुक्त (2) मामले में 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' के बाद के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें उस अदालत के अधिकारियों के पिछले पाठ्यक्रम से हटकर, विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह माना गया था कि अपीलीय सहायक आयुक्त का एक अपील को समय-बाधित के रूप में खारिज करने का आदेश धारा 30(2) के तहत था, न कि धारा 31 के तहत, और इसलिए अपील योग्य नहीं था। आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम माउंट मामले में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों के कारण उन्होंने खुद को इस निष्कर्ष को अपनाने के लिए बाध्य महसूस किया। अर. एस. अर. अरुणाचलम चेट्टियार(3). लेकिन जब उस मुद्दे के संदर्भ में पढ़ा जाता है जो वास्तव में उस मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न हुआ था, तो वे टिप्पणियाँ विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष का कोई समर्थन नहीं करती हैं। वहाँ, तथ्य यह थे कि आयकर अधिकारी के एक आदेश के खिलाफ धारा 30(1) के तहत

निर्धारिती द्वारा अपील की गई थी , और अपीलीय सहायक आयुक्त ने 19-11-1945 को इसे अक्षम बताते हुए खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई और यह अंतिम हो गया। लेकिन दिनांक 19-11-1945 के आदेश में दिए गए एक सुझाव पर कार्रवाई करते हुए, निर्धारिती ने राहत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल विविध आवेदन दायर किया, और अपने आदेश दिनांक 20-2-1946 द्वारा न्यायाधिकरण ने आय के निष्कर्षों को अलग कर दिया- कर अधिकारी को निर्देश दिया कि नये सिरे से गणना करें। फिर, आयकर आयुक्त के आवेदन पर, ट्रिब्यूनल ने आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के तहत उच्च न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्न भेजा: "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, का आदेश बेंच दिनांक 20 फरवरी, (1) [1950] 18 आईटीआर 204, 212। (2) [1955] 27 आईटीआर 268। (3) [1953] एससीआर 463: 474-475, 1946 विविध आवेदन में एक उचित आदेश है और कानूनी रूप से वैध है और अधिकार क्षेत्र के भीतर पारित किया गया है और आयकर अधिकारी पर बाध्यकारी है"। उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ का उत्तर देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि ट्रिब्यूनल का आदेश धारा 33(1) के तहत अपील में पारित नहीं किया गया था , और इसके परिणामस्वरूप, धारा 66(1) के तहत संदर्भ दिया गया था। स्वयं अक्षम था। इस निर्णय की सत्यता को इस न्यायालय में अपील पर चुनौती दी गई थी, और इसकी पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने कहा: ..... जब 19 नवंबर 1945 को, अपीलीय सहायक आयुक्त ने अपील स्वीकार करने से इनकार

कर दिया, तो निर्धारिती ने ऐसा किया उन्होंने कोई अपील नहीं की बल्कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष केवल एक विविध आवेदन किया। अधिनियम में ऐसे आवेदन की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल, मामले के बयान में अपीलीय न्यायाधिकरण का कहना है कि उस आवेदन पर विचार करने और आयकर अधिकारी की त्रुटि को सुधारने में उसने अपनी अंतर्निहित शक्तियों के रूप में कार्य किया। धारा 33(1) के तहत कोई अपील नहीं है और आदेश अपने कथित अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया गया है, आदेश को संभवतः धारा 33(4) के तहत एक नहीं माना जा सकता है और धारा 33(4) के तहत कोई आदेश नहीं है। धारा 66(1) या (2) के तहत कोई संदर्भ नहीं हो सकता है, और अपीलीय न्यायालय ने इस पर विचार करने से उचित रूप से इनकार कर दिया"।

निःसंदेह, निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस समय चर्चा के बिंदु से मेल खाता हो। लेकिन पृष्ठ 474 और 475 पर होने वाली कुछ टिप्पणियों को विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए संदर्भित किया गया था कि समय-बाधित अपील को खारिज करने वाला आदेश धारा 3ओ(2) के अंतर्गत आएगा। अब, वे टिप्पणियाँ अपील के समर्थन में विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा प्रस्तुत एक नए तर्क के उत्तर के रूप में की गईं। वह तर्क यह था कि ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत विविध आवेदन को 19-11-1945 के आदेश के खिलाफ अपील के रूप में माना जा सकता है,

ऐसी स्थिति में 20-2-1946 को पारित आदेश धारा 33(4) के अंतर्गत आएगा और संदर्भ कॉम होगा-

इस तर्क से असहमत होते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलीय सहायक आयुक्त की अपील धारा 30(1) के तहत अक्षम थी , भले ही यह सक्षम थी, दिनांक 19-11-1945 का आदेश धारा 31 द्वारा विचारित नहीं था , और धारा 33(1) के तहत ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। अब, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वास्तव में धारा 66(1) के तहत संदर्भित प्रश्न एक विविध आवेदन में पारित आदेश की शुद्धता और वैधता का था, न कि धारा 33(1) के तहत की गई अपील में किए गए किसी आदेश का । इस संदर्भ में, विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा उठाया गया मुद्दा निर्णय के लिए आया ही नहीं, और उसके उत्तर में की गई टिप्पणियों को अपील की विचारणीयता के प्रश्न पर एक घोषणा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सकता है। यह निर्णय कि किसी अपील को परिसीमा द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने का आदेश धारा 30(2) के अंतर्गत एक है ।तदनुसार, यह प्रश्न कि क्या परिसीमा के कारण अपील को खारिज करने वाला आदेश धारा 30(2) या धारा 31 के अंतर्गत आता है, आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम माउंट में टिप्पणियों से अप्रभावित रहता है। अर. एस. अर. अरुणा- चलम चेट्टियार(1).

फिर, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, परिसीमा ही एकमात्र प्रारंभिक आधार नहीं है जिस पर योग्यता पर विचार किए बिना अपील का

निपटारा किया जा सकता है। धारा 30(3) में प्रावधान है कि "अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी और निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी"। यदि अपीलीय सहायक आयुक्त यह मानता है कि अपील इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है और उस आधार पर इसे खारिज कर देती है, तो आदेश धारा 31 के तहत दिया गया आदेश होना चाहिए, क्योंकि धारा 30(3) ऐसे आदेश के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, जैसा कि सीमा के मामले में धारा 30(2) करता है। धारा 31 के तहत सभी आदेश धारा 33 के तहत अपील योग्य हैं, धारा 30 (3) के गैर-अनुपालन के लिए बर्खास्तगी का आदेश भी अपील योग्य होना चाहिए, और महारानी ज्ञान मंजरी कुआरी बनाम आयकर आयुक्त (2) मामले में ऐसा निर्णय लिया गया था। इस दृष्टिकोण को इस तर्क के साथ कैसे समेटा जा सकता है कि धारा 31 केवल (1) [1953] एससीआर 463 पर आदेशों पर विचार करती है। (2) (1944) 12 आईटीआर 59।

मूल्यांकन के गुण और प्रारंभिक मुद्दों पर नहीं? कुँवरजी आनंद बनाम आयकर आयुक्त (1) में भी निर्णय देखा गया, जिसका पालन महारानी ज्ञान मंजरी कुआरी बनाम आयकर आयुक्त (2) और रामनारायण दास मंडल बनाम आयकर आयुक्त में किया गया। 3). इस प्रकार इस स्थिति के लिए प्रचुर अधिकार है कि धारा 31 की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इसमें न केवल मूल्यांकन के गुणों पर विचार करते हुए पारित आदेश

शामिल हों बल्कि ऐसे आदेश भी शामिल हों जो प्रारंभिक मुद्दों, जैसे सीमा और इसी तरह की अपील का निपटान करते हैं। .

विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने इन निर्णयों पर काबू पाने की मांग की, धारा 31(3) (ए) के शाब्दिक और सामान्य अर्थों में, अपीलीय सहायक आयुक्त को केवल मूल्यांकन के गुणों के आधार पर आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया। , इसलिए उसके लिए ऐसे किसी भी प्रश्न पर विचार करना खुला नहीं था जो सीधे तौर पर ऐसे गुणों से संबंधित नहीं था, और तदनुसार वह परिसीमन जैसी प्रारंभिक प्रकृति के किसी भी मुद्दे को सुन या तय नहीं कर सकता था, और आधार पर अपील का निपटान नहीं कर सकता था। उस मुद्दे पर निष्कर्ष का. उन्होंने स्वीकार किया कि यह विवाद कई प्राधिकारियों के विपरीत होगा, लेकिन तर्क दिया कि वे सभी गलत थे। इस विवाद पर उचित विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह उचित नहीं है।

परिसीमा की दलील लेते हुए - इस अपील में हम इसी से चिंतित हैं जब कोई निर्णय या आदेश होता है जिसके खिलाफ कानून अपील का अधिकार प्रदान करता है लेकिन उसके लिए निर्धारित समय के भीतर किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो प्रतिवादी एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त कर लेता है। जिससे उसे देरी को माफ करने और उसकी पीठ पीछे अपील स्वीकार करने के आदेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। और जब ऐसा कोई आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है तो

उसे अपील के समय इसकी सत्यता को चुनौती देने का अधिकार है। यह सामान्य कानून के तहत स्थिति है (कृष्णासामी। पणिकोंदर बनाम रामासामी चेट्टियार (4) के तहत), और आयकर अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक अलग सिद्धांत लागू करता हो। (1) आई एलआर 11 पटना 187; एआईआर 1931 पटना 306; 5 आईटीसी

417. (2) [1944]12 आईटीआर 59. (3) (1950) 18 आईटीआर 660। (4) [1918] आईएलआर 41 मैड। 412; 45 आईए 25.

इसलिए, यदि प्रस्तुति में देरी के तथ्य पर ध्यान दिए बिना किसी अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्पष्ट रूप से अपील की सुनवाई के समय आपत्ति उठाने के लिए विभाग के पास खुला होना चाहिए। वह भी पहले प्राप्त करने का अभ्यास ही प्रतीत होगा। आयकर न्यायाधिकरण, जैसा कि हमारे सामने उद्धृत निर्णयों से प्रतीत होता है, और वह, हमारी राय में, सही है। इसी तरह के विचार प्रारंभिक चरित्र की अन्य आपत्तियों पर भी लागू होंगे, जैसे कि धारा 30, उप-धारा (3) पर आधारित। हमें ऐसे निर्माण को अपनाने में धीमा होना चाहिए जो पार्टियों को मूल्यवान अधिकारों से वंचित करता है। इसलिए हमारी राय है कि प्रारंभिक मुद्दों से संबंधित विवाद अपील की सुनवाई के समय विचार के लिए खुले हैं, और अपीलीय सहायक आयुक्त का अधिकार क्षेत्र केवल मूल्यांकन के गुण-दोष के आधार पर अपील करने तक सीमित नहीं है। इस दृष्टि से, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश यह मानते हुए कि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त

कारण नहीं थे और समय-बाधित के रूप में अपील को खारिज कर दिया जाएगा , धारा 31 के तहत पारित आदेश होंगे और अपील के लिए खुले होंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस स्थिति में कि क्या बर्खास्तगी का आदेश अपील स्वीकार होने से पहले किया गया है या बाद में।

तदनुसार संदर्भित प्रश्न का उत्तर हां में दिया जाना चाहिए। इसलिए यह अपील स्वीकार की जाएगी और निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता को अपनी लागत यहां और नीचे की अदालत में भुगतनी होगी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी चरण आशा (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।